

सर्वोच्च न्यायालय ने IBC के प्रमुख प्रावधानों को बरकरार रखा

प्रलिस के लिये:

सर्वोच्च न्यायालय, IBC के प्रमुख प्रावधान, दवाला और दवालियापन संहिता (IBC), अनुच्छेद 21, व्यक्तिगत गारंटर ।

मेन्स के लिये:

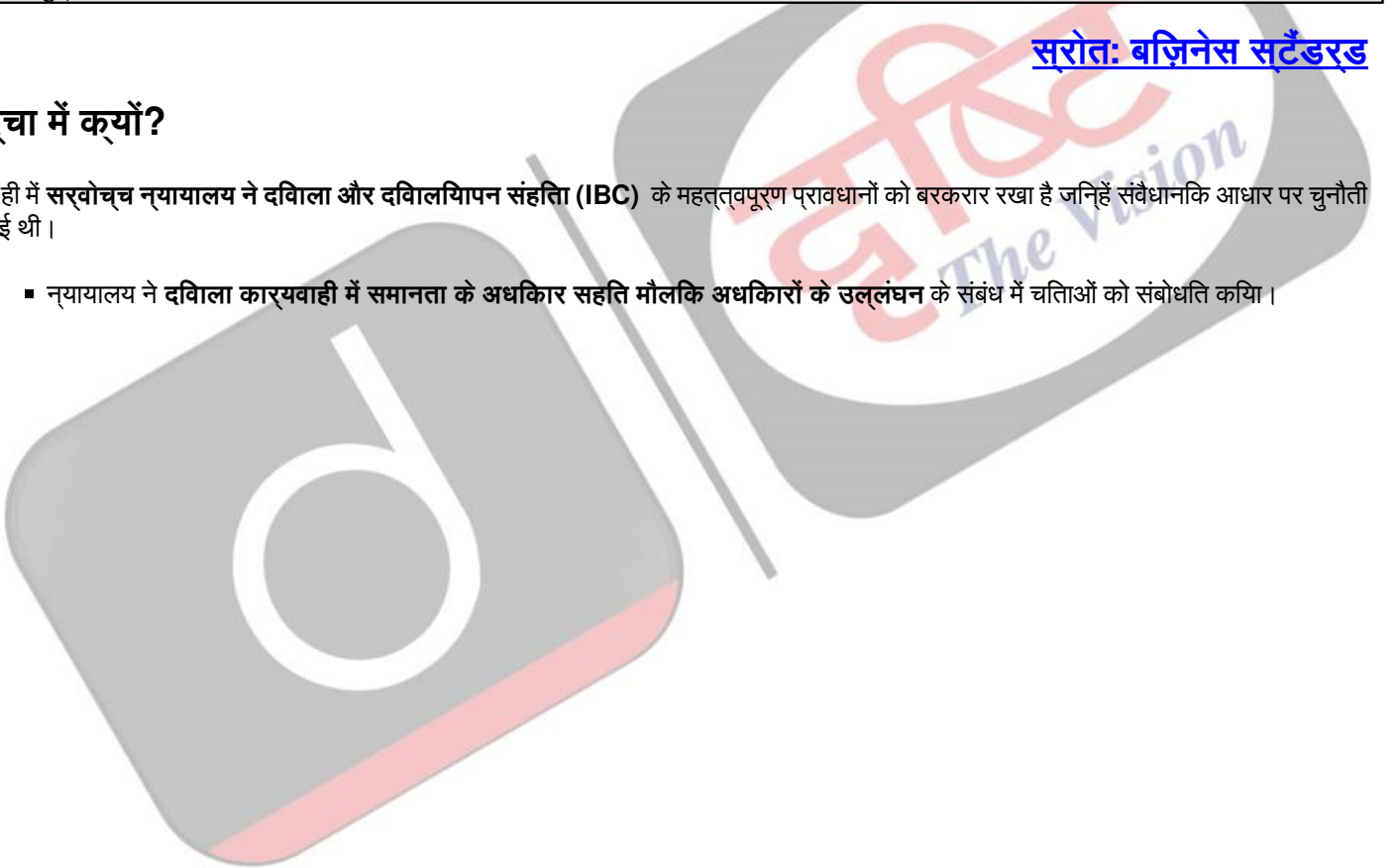
सर्वोच्च न्यायालय ने IBC के प्रमुख प्रावधानों को बरकरार रखा, भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधन जुटाने, वृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे ।

[स्रोत: बज़िनेस स्टैंडर्ड](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने दवाला और दवालियापन संहिता (IBC) के महत्वपूर्ण प्रावधानों को बरकरार रखा है जिन्हें संवैधानिक आधार पर चुनौती दी गई थी ।

- न्यायालय ने दवाला कार्यवाही में समानता के अधिकार सहित मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में चर्चाओं को संबोधित किया ।



THE FINE PRINT

What's the case

- ▶ Petitioners had challenged the constitutional validity of IBC provisions
- ▶ Personal guarantors were not given an opportunity to present their case or contend the initiation of insolvency process, they said

SC ruling

- ▶ IBC does not suffer from the vices of manifest arbitrariness
- ▶ RP not intended to perform an adjudicatory function

Impact of judgment

- ▶ Relief for lenders
- ▶ Setback for promoters who have guaranteed debt
- ▶ Experts say IBC timelines would be met



याचिकाओं और सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों से क्या चर्चा बढ़ी है?

■ याचिकाकर्ताओं के तर्क:

- प्रमुख मुद्दा यह था कि **व्यक्तिगत गारंटर को अपना मामला पेश करने या दवाला समाधान प्रक्रिया** की शुरुआत का विरोध करने या **रजिस्ट्रेशन प्रोफेशनल (RP)** की नियुक्ति में अपनी बात रखने का अवसर नहीं दिया गया था।
 - व्यक्तिगत गारंटर वह व्यक्ति होता है जो **किसी अन्य पक्ष द्वारा लिये गए ऋण या वित्तीय दायित्व हेतु व्यक्तिगत गारंटी प्रदान करता है**। जब कोई व्यक्ति धन उधार लेता है या ऋण प्राप्त करता है, तो ऋणदाता को सुरक्षा के रूप में व्यक्तिगत गारंटी की आवश्यकता हो सकती है।
- याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि **दवाला और दवालियापन संहिता (Insolvency and Bankruptcy Code- IBC)** के चुनौती वाले हिस्से नृषिपक्ष सिद्धांतों (प्राकृतिक न्याय) का पालन नहीं करते हैं तथा संवधान के **अनुच्छेद 21**, 19(1)(g) एवं 14 के तहत आजीविका, व्यापार और समानता के अधिकार जैसे **मौलिक अधिकारों** को प्रभावित करते हैं।

■ न्यायालय की टिप्पणी:

- **संवैधानिकता और व्यक्तिगत गारंटर:** न्यायालय ने IBC के प्रमुख प्रावधानों की संवैधानिकता को बरकरार रखा, जिसमें व्यक्तिगत गारंटर के खिलाफ दवालिया कार्यवाही की अनुमति भी शामिल है।
 - न्यायालय ने नृषिणय सुनाया कि IBC पूर्वव्यापी नहीं है और माना कि धारा 95 से 100 को सरिफ इसलिये असंवैधानिक नहीं माना जा सकता क्योंकि वे **व्यक्तिगत गारंटर्स को लेनदारों की दवालिया संबंधी याचिकाओं से पहले सुनवाई का मौका नहीं देते**

- हैं।
- इसने उन दावों के खिलाफ नरिणय सुनाया कि इन प्रावधानों में नषिपक्षता की कमी है या प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन हुआ है, यह कहते हुए कि नषिपक्षता का मूल्यांकन मामले-दर-मामले किया जाना चाहिये।
- रजिऑल्यूशन प्रोफेशनलस (RP) की भूमिका: न्यायालय ने RP की नयुक्तिसे पहले न्यायिक हस्तक्षेप को शामिल करने के वचिार को खारजि कर दिया, यह कहते हुए कि एक नश्चिति अनुभाग से पहले एक न्यायिक भूमिका जोड़ने से IBC की नरिधारति समय-सीमा बाधति हो जाएगी।
 - यह स्पष्ट कर दिया गया था कि RP सूचना एकत्र करने वाले और सफिराशि करने वाले सुवधि प्रदाता हैं, नरिणय लेने वाले नहीं।
- अधस्थिगन प्रावधान: न्यायालय इस बात पर सहमत हुआ कि ये प्रावधान मुख्य रूप से देनदारों के बजाय ऋणों की रक्षा करते हैं।
 - इसने वधियिका के नरिणयों का समर्थन किया कि कब अधस्थिगन लागू होना चाहिये और IBC में व्यक्तगित देनदारों, भागीदारों एवं कॉर्पोरेट देनदारों के बीच मतभेदों पर प्रकाश डाला।

IBC पर SC के नरिणय का संभावति प्रभाव क्या हो सकता है?

- लेनदार का वशिवास:**
 - IBC के प्रावधानों की पुष्टि, वशिष रूप से व्यक्तगित गारंटियों के संबंध में लेनदार का वशिवास बढ़ सकता है।
 - गारंटियों के खिलाफ दवािलयिा कार्यवाही शुरू करने के वषिय में लेनदार अधिक सुरक्षति महसूस करेंगे, जसिसे संभावति रूप से ऋण की वसूली में अधिक मुखर दृष्टिकोण अपनाया जा सकेगा।
- स्पष्टता और पूर्वानुमेयता:**
 - न्यायालय के नरिणय द्वारा प्रदान की गई स्पष्टता दवािला ढाँचे के अंदर पूर्वानुमान को बढ़ा सकती है। यहसहज और अधिक कुशल समाधान प्रकरयिाओं को प्रोत्साहित कर सकता है, उन अनश्चितताओं को कम कर सकता है जो पहले लेनदार के कार्य में बाधा बन सकती थीं।
- समर्थकों को सतर्क करना:**
 - यह नरिणय समर्थकों और कॉर्पोरेट ऋणों के लयि व्यक्तगित गारंटी प्रदान करने वाले व्यक्तयिों को सावधान करेगा।
 - समर्थक, यहाँ तक कि सॉल्वेंट कंपनयिों के मामले में भी वे इस नरिणय द्वारा उजागर संभावति जोखमिों के कारणव्यक्तगित गारंटी देने के वषिय में अधिक सतर्क हो सकते हैं।

दवािला और शोधन अक्षमता संहति, 2016 क्या है?

- सरकार ने दवािला और शोधन अक्षमता संहति से संबंधति सभी कानूनों को समेकति करने तथा गैर-नषिपादति परसिंपतयिों (NPA) से नषिटने के लयि IBC, 2016 को लागू किया, यह एक ऐसी समस्या है जो वर्षों से भारतीय अर्थव्यवस्था में गरिावट ला रही है।
 - दवािला एक ऐसी स्थति है जसिमें व्यक्त अथवा कंपनयिा अपना परादेय ऋण/बकाया ऋण (Outstanding Debt) चुकाने में असमर्थ होती है।
 - शोधन अक्षमता एक ऐसी स्थति है जसिमें सक्षम अधिकारति (Competent Jurisdiction) वाले न्यायालय में कसिी व्यक्त अथवा अन्य संस्था को दवािलयिा घोषति कर दिया जाता है, इसे हल करने तथा लेनदारों के अधिकारों की रक्षा करने के लयि उचित आदेश पारति कयि गए हैं। यह ऋण चुकाने में असमर्थता की वधिकि घोषणा है।
- IBC सभी व्यक्तयिों, कंपनयिों, सीमति देयता भागीदारी (LLP) और साझेदारी फर्मों को कवर करता है।
 - न्याय-नरिणयन प्राधकिारी:
 - कंपनयिों तथा LLP के लयि राष्ट्रीय कंपनी वधि अधकिरण (NCLT)।
 - व्यक्तयिों तथा साझेदारी फर्मों के लयि ऋण वसूली अधकिरण (DRT)।

वधिकि अंतरदृष्टि:

[महतत्वपूर्ण संस्थानों के बारे में वसितार से पढ़ें:](#)

- [राष्ट्रीय कंपनी वधि अधकिरण](#)

www.drishtijudiciary.com

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. नमिनलखति कथनों में से कौन-सा हाल ही में समाचारों में आए 'दबावयुक्त परसिंपतयिों के धारणीय संरचन पद्धतति (स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरगि ऑफ स्ट्रेसड एसेट्स/S4A)' का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है? (2017)

- यह सरकार द्वारा नरिपति वकिसात्तमक योजनाओं की पारस्थितिकिय कीमतों पर वचिार करने की पद्धतति है।
- यह वास्तवकि कठनाइयों का सामना कर रही बड़ी कॉर्पोरेट इकाइयों की वत्तीय संरचना के पुनर्संरचन के लयि भारतीय रजिर्व बैंक की स्कीम है।
- यह केंद्रीय सार्वजनकि क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में सरकार की एक वनिविश योजना है।

(d) यह सरकार द्वारा हाल ही में क्रियान्वृति 'द इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड' का एक महत्त्वपूर्ण उपबंध है ।

उत्तर: (b)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/supreme-court-upholds-key-provisions-of-ibc>

